रविवारीय

विनाशकारी अनिश्चितता के भंवर में फंसा बांग्लादेश

विजय कुमार झा

एक समय अपनी तीव्र आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुधारों के लिए दक्षिण एशिया में मिसाल के तौर पर देखा जाने वाला बांग्लादेश आज विनाशकारी अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है. अगस्त 2024 में व्यापक छात्र विरोध और उसके बाद उपजी हिंसा के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्ता छोड़ना और भारत में शरण लेना एक ऐसी घटना थी, जिसने न केवल ढाका की सत्ता बदली, बल्कि पूरे देश की दिशा ही बदल दी. नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार से दुनिया को उम्मीद थी कि वह देश को स्थिरता और लोकतंत्र की ओर ले जाएगी, लेकिन बीते कुछ महीनों के घटनाक्रम बताते हैं कि यह उम्मीदें पूरी तरह निरर्थक साबित हुई हैं. आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां प्रगति की बातें बेमानी हो चुकी हैं और देश उन कट्टरपंथी ताकतों के वर्चस्व में है, जिन्हें खुले तौर पर पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी माना जाता है.

कूटनीतिक तनाव और सुरक्षा पर खतरा- भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों में वर्तमान दौर सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुआ खतरा इस बात का प्रमाण है कि वहां की अंतरिम सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है. हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारतीय उच्चायोग को लगातार मिल रही धमकियां और कट्टरपंथियों के निशाने पर होना किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है. हैरानी की बात यह है कि यूनुस सरकार इन तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है. सुरक्षा कारणों से भारत को ढाका के जमुना पार्क स्थित अपने वीजा सेंटर को बंद करने का कड़ा फैसला लेना पड़ा है. वहां एक कट्टरपंथी संगठन ने प्रदर्शन कर मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश के हवाले किया जाए. विडंबना देखिए कि जिस देश ने भारत के सहयोग से स्वतंत्रता की सांस ली, वहां पिछले 16 महीनों में भारत विरोधी 10 बड़े प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अंतरिम प्रशासन ने अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है. इसके विपरीत, 54 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार शुरू होना इस बात को स्पष्ट करता है कि ढाका की नई सत्ता का झुकाव किस ओर है.

बंगबंधु की विरासत पर प्रहार - डॉ. मोहम्मद यूनुस से निष्पक्षता की अपेक्षा थी, लेकिन उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान (बंगबंधु) की विरासत को व्यवस्थित तरीके से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है. शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे दर्ज करना और उन्हें फांसी की सजा सुनाया जाना केवल राजनीतिक प्रतिशोध है. यह स्थिति उन कट्टरपंथी समूहों को वैधता प्रदान कर रही है, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की मूल भावनाओं और धर्मनिरपेक्षता के कट्टर दुश्मन रहे हैं. आज बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला किया जा रहा है.

शरीयत आधारित शासन की वकालत- अंतरिम सरकार के साये में जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रतिबंधित और कट्टरपंथी संगठन न केवल मुख्यधारा में लौट आए हैं, बल्कि अब वे खुलकर शरीयत आधारित शासन की वकालत कर रहे हैं. इन समूहों का बढ़ता प्रभाव देश के अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के लिए काल बन गया है. मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और शरिया कानून लागू करने की सुगबुगाहट ने देश के सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न-भिन्न कर दिया है. राजनीतिक मोर्चे पर भी संकट कम नहीं है. चुनाव आयोग ने फरवरी 2026 में आम चुनाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अवामी लीग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. उनका आरोप है कि एक किलर-फासीस्ट गिरोह की तरह काम कर रही यह सरकार निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकती. जब देश की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति को प्रक्रिया से बाहर रखने के प्रयास हों, तो उस चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है.

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चेतावनी- कुल मिलाकर, डॉ. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश को स्थिरता देने के बजाय अराजकता की ओर ले गई है. कट्टरपंथियों को दिया गया मौन समर्थन और भारत विरोधी एजेंडा न केवल बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र को नष्ट कर रहा है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है. बांग्लादेश आज गृह-युद्ध जैसी स्थिति की दहलीज पर है. यदि समय रहते अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वहां की सरकार ने कट्टरपंथ पर अंकुश नहीं लगाया, तो यह देश न केवल अपनी पहचान खो देगा, बल्कि एक अस्थिर पड़ोसी के रूप में भारत के लिए भी एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बना रहेगा.

> आर्थिक पतन-विकास से विनाश की ओर राजनीतिक अस्थिरता का सबसे वीभत्स रूप बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है. शेख हसीना के शासनकाल में जिस बांग्लादेश को इकोनॉमिक टाइगर कहा जाता था, वह आज भीख का कटोरा लेकर खड़ा है. पिछले पांच वर्षों में देश का बाहरी कर्ज 42प्रतिशत तक बढ़ गया है. विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और कर्ज चुकाने की अक्षमता ने देश को दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 4ब्न से भी कम कर दिया है. यह गिरावट किसी भी विकासशील देश के लिए खतरे की घंटी है. देश में मुद्रास्फीति 9प्रतिशत के पार जा चुकी है. खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता में भारी असंतोष है. हिंसा और अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशकों ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है. नई पूंजी के अभाव में उद्योग-धंधे ठप पड़ रहे हैं.

सीएम डॉ. मोहन ने दिया नववर्ष का मेट्रो तोहफा

राकेश शर्मा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भोपालवासियों का सबसे बड़ा सपना मेट्रो भोपाल में चले,उसे पूरा कर दिया है. जब भी कोई भी भोपालवासी दिल्ली जाता था तो लौट कर दिल्ली मेट्रो की तारीफ करता था और विचार करता था कि हमारे लाडले शहर भोपाल में कब मेट्रो चलेगी. जिस तरह से भोपाल शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तो भोपालवसियों के सुगम यातायात के लिए मेट्रो की आवश्यकता महसूस हुई.

कुछ लोग अभी भी अपनी बातों में कहते हैं कि ये तो मात्र 7.2 किलोमीटर ही है इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये शहर का बहुत छोटा एरिया कवर कर रही हैद्य एसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह नहीं भूलना चाहिए कि जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वहां भी 8.3 किलोमीटर से शुरुआत हुई थी.आने वाले समय में मेट्रो भोपालवासियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी. मेट्रो का संचालन सुबह 8ः00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा. इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक एयर कंडीशनर कोच, हाई स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर आधारित सुरक्षा एवं प्लेटफार्म की स्कीम डोर्स और दिव्यांगजन हेतु हर तरह की सुविधा सहज उपलब्ध होगी. 7 किलोमीटर में आठ एलिवेटेड स्टेशन, ऑडियो विजुअल पैसेंजर सूचना प्रणाली ,समर्पित लास्ट स्माइल कनेक्टिविटी,तेज,सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा यात्रा के समय में कमी,सड़क ट्रैफिक से राहत और आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक भोपाल मेट्रो को बनाया गया है. भोपाल मेट्रो एक ओर जहाँ हाईटेक है वहीं ये पूर्णत: स्वदेशी है, इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत गुजरात में किया गया है इसके सारे के सारे कोच देश में गुजरात के सांवली प्लांट में बनाए गए हैं.

आज का दिन भोपालवासियों के लिए एक यादगार पल रहेगा जो उनके जीवन में अमिट छाप छोड़ेगा. भोपालवासी अपनी आने वाली पीढ़ी को गर्व से बता पाएंगे कि भोपाल की जो मेट्रो वह आज देख रहे हैं इसकी शुरुआत और निर्माण उनके के सामने हुआ और वह उसके साक्षी रहे हैं. 20 दिसंबर शाम 4ः00 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में शिरकत करेंगेंद्य कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भोपाल मेट्रो में बैठकर सफर की शुरुआत करेंगे.

अभी शुरुआत एम्स से सुभाष नगर तक की जा रही है आने वाले समय में इसका और भी विस्तार होगा जिसका काम शहर में चारों तरफ तेजी से चल रहा है .भदभदा रोड ,करोद ,आईटीआई गोविंदपुरा एवं अन्य स्थानों पर तेजी से मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है.आने वाले समय में पूरा शहर भोपाल मेट्रो से जुड़ जाएगा. मेट्रो ट्रेन में तीन कोच होंगे जिसमें 250 यात्री सफर कर सकेंगें.आने वाले समय में 27 ट्रेन भोपाल में चलेगी मेट्रो ट्रेन आने वाले समय में भोपाल की पहचान बनेगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश के दूर दराज शहरों से है और देश के कई शहरों से लोग भोपाल आते हैं उनके लिए मेट्रो वरदान साबित होगी .

भोपाल मेट्रो भोपालवासियों के लिए आने वाले नए वर्ष का एडवांस में ही तोहफा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास पुरुष और प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए सतत प्रयास करने वाले डॉक्टर मोहन यादव की सौगात है. आज भोपाल का हर वासी अपने लाडले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का शुक्रिया अदा कर रहा है. भोपाल में मेट्रो के लिए धन्यवाद डॉ मोहन यादव जी भोपाल को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए.

व्यंग्य

मन..रे..गा अब, जी राम जी...(टेक)

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

आज देश में संसद से लेकर सड़क तक राम नाम की चर्चा है. कहीं राम से रार है तो कहीं राम से प्यार है. भारत के घट घट में राम ही राम है.मरते राम,जीते राम हंसते और हंसाते राम. करोड़ों लोग राम को भगवान मनाते हैं तो विधर्मी राम को इमाम मानते हैं. राम के अस्तित्व को न तो कोई नकार पाया है और न ही नकार सकता है. जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल लगाया उनका यह हाल है कि वो पिछले 11 सालों से उनका हाल बे हाल हैं. वे पूरे देश में मारे मारे फिर कर गाते फिर रहे हैं - नसीब साडा चोरी हो गया अब कि करियां कि करियां..... जिस तरह जादूगरनी की जान तोते में होती थी उसी तरह नेताओं की जान अब वोट में रहती है.

केंद्र की गद्दी पर जब से मोदी नाम का मैजिशियन बैठा है उससे पुराने सियासी जादूगर बेदम पड़े हैं. जब यूपीए सरकार ने कोरट में कहा था कि राम का कोई अस्तित्व था ही नहीं वो तो किस्से कहानी में है. उनका तो कोई अस्तित्व पहले था और न अब है. वही लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राम जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जिस तरह राम जी वनवास काट कर और लंका विजय कर 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे. उसी तरह राम भक्तों की टोली अपनी पार्टी यानि भाजपा के गठन के 14 सालों बाद सन् 2014 में राम जी के अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग भारत के केंद्र में विजय हो कर सत्ता में लौट आए. लौटे तो ऐसे लौटे कि सब तर? राम ही राम हो गए. पूरा देश राम मय हो गया.

लंका विजय से पूर्व राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व जिस तरह समुद्र तट शिवलिंग की आराधना करने के बाद सेतुबंध रामेश्वरम के निर्माण की पूजा अर्चना की थीं. लगभग उसी की पुनरावृति मंगलवार 16 दिसंबर को लोकसभा में उस समय देखने को मिली जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन रे गा में जी राम जी को जोड़ दिया. जो राम जी समर्थक और विरोधी सब लोकसभा में एक स्वर में स्वत- जपने लगे मन रे गा जी राम जी. कुछ विरोध में गा रहे थे तो कुछ समर्थन प्रसन्न हो कर भजन सा कर रहे थे मन..रे..गा..जी राम जी. भाई भाजपा वाले हैं तो कलाकार आखिर विरोधियों से भी कहलवा ही दिया, क्या कहलवा दिया ? मन..रे ..गा, जी राम जी. इसका भावार्थ यह हुआ कि- ऐ मन रे (तू) जी राम जी गा, इसी से तेरे मन को शांति मिलेगी.

यह वह देश हैं जिसके रोम रोम में राम हैं. यहां के कण कण में और घट घट में राम बसते हैं. यहां वादन में भी राम हैं और रुदन में भी राम हैं. इसे इस तरह भी कहा जा सकता है. महिमा मेरे राम की जीत देखूं तित राम. संत कबीर ने राम को अलग दृष्टि से देखा है. उन्होंने कहा कि मोमे तोमे सरब में,जहं देखें तं राम . राम बिना क्षण एक ही, सरे न एको काम.. राम नाम की महिमा पर कबीर ने लिखा राम भजी मन बसि करो, ये ही बड़ा अरंथ. काहे को पढ़ी पढ़ी मरो, कोटिक ज्ञान ही गिरंथ . कबीर साहब लिखते हैं - एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, राम रहीमा ऐक है, नाम धराया दोई. राम सर्वव्यापी हैं .आज भले ही मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को राम नाम से परहेज हो पर संत रहीम खान खाना ने लिखा गहि शरणागति राम की, भवसागर की नाव. रहिमन जगत उधार कर, और न कछु उपाव.

माधुरी दीक्षित को तेज़ाब फिल्म में अपने पिया में ही राम दिखाई देते हैं. तभी तो उसने खुशी से कमर मटका मटका कर के गाया था. मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया. पिया के आने की खुशी किस को नहीं होती. मीरा ने कृष्ण में पिया पाया (यानि देखा), तभी तो उन्होंने निःसंकोच जहर का प्याला भी पी लिया .मेरे शहर में एक लोकल कवि थे शरद दीक्षित उनकी एक कविता थी- आजकल की त्रियन को पियन की चाह है, बाजार में पूछत हैं लिपटन की चाह है. आजकल की तिरयन की बात अलग है उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है वह सशक्त हो गईं हैं कि पिया अशक्त हो गए हैं.

पहले की तिरयन राम रस का पान करतीं थीं और आज की त्रिया रमी खेलतीं हैं राम रस की जगह अब रम रस का पान करतीं हैं. पहले उनकी आंखों में लाज हुआ करतीं थीं अब उनको देख कर लाज को भी लाज आने लगी है. पहले उनके लिए साहित्य में एक शब्द था लाजवंती का. अब लाणबंदी हो गया है. वे खुले पन की एक्जीविशन हो गईं है. इस संदर्भ में एक गुमनाम से कवि की कुछ लाइनें याद आ रही हैं. वो इस तरह हैं ,-आज़ादी कुछ ऐसी आई कि युग सारा बदनाम हो गया, धरा भिखारिन बन बैठी और जग सारा बदनाम हो गया. शायद इन्हीं हालातों को देखकर रहीम दास जी ने कहा था रहिमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फैर, जब नीके दिन आईहैं, बनत ना लगि हैं देर .

बुद्धिजीवियों और विद्वानों में इस बात पर अलग अलग राय हो सकतीं हैं कि जो लाइनें रहीम दास जी के नाम से लिखीं है वे रहीमदास की नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं. तो भाइयों इसमें काहे का विवाद दोनों ही कवि थे राम भक्त थे. दोनों ही संत थे. दोनों ही कवि हैं और दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं. कोई भी दावा करने नहीं आएगा कि भैया ये लाइनें मेरी हैं उनकी नहीं है. लड़ो तो इस बात के लिए लड़ो कि इनमें एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान. क्योंकि भैया लड़ाई का यही ट्रेंड चल रहा है. इसी लूट में आप और हम दोनों शामिल हो जाएं.

नितिन नबीन की नियुक्ति और भाजपा की बदली नेतृत्व रणनीति

श्याम यादव

भाजपा की परंपरा में 'कार्यकारी अध्यक्ष' का पद महज़ अस्थायी या औपचारिक भूमिका नहीं रहा है. पार्टी के इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां पहले किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वही पूर्ण अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालता दिखाई दिया. इस दृष्टि से नितिन नबीन की नियुक्ति को एक प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें नेतृत्व यह परखता है कि कोई व्यक्ति विवादों से दूर रहकर, बिना स्वतंत्र राजनीतिक रेखा खींचे, संगठन को कितनी कुशलता से संभाल सकता है.

ऐसा संगठनात्मक फैसला किया है, जिसे केवल युवा नेतृत्व को आगे लाने की सामान्य प्रक्रिया मान लेना पर्याप्त नहीं होगा. यह नियुक्ति भाजपा की वर्तमान राजनीतिक सोच, नेतृत्व चयन की कार्यप्रणाली और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति को एक साथ समझने का अवसर देती है. नितिन नबीन न तो राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थापित चेहरा हैं और न ही बिहार की राजनीति में उन्हें किसी बड़े जनाधार वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा है. इसके बावजूद उन्हें पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक ढांचे में शामिल किया जाना इस बात का संकेत है कि भाजपा में अब नेतृत्व चयन का आधार करिश्मा या चुनावी लोकप्रियता नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और शीर्ष नेतृत्व के प्रति भरोसा बन चुका है. भाजपा की परंपरा में 'कार्यकारी अध्यक्ष' का पद महज़ अस्थायी या औपचारिक भूमिका नहीं रहा है. पार्टी के इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां पहले किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वही पूर्ण अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालता दिखाई दिया. इस दृष्टि से नितिन नबीन की नियुक्ति को एक प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें नेतृत्व यह परखता है कि कोई व्यक्ति विवादों से दूर रहकर, बिना स्वतंत्र राजनीतिक रेखा खींचे, संगठन को कितनी कुशलता से संभाल सकता है.

नितिन नबीन का राजनीतिक जीवन इसी प्रकार के संगठनात्मक व्यवहार से पहचाना जाता है. वे पार्टी लाइन से अलग कोई मुखर या स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नहीं जाने जाते. भाजपा जैसी केंद्रीयकृत पार्टी संरचना में यह गुण नेतृत्व के लिए भरोसे का आधार बनता है. इस नियुक्ति का एक अहम पहलू बिहार की राजनीति से भी जुड़ा है. बिहार में भाजपा लंबे समय से नेतृत्व के संकट से जूझ रही है. पार्टी के पास वहां ठोस संगठन और मतदाता आधार तो है, लेकिन ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिसे वह मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा सके. गठबंधन राजनीति और उसके टूटते-बनते समीकरणों ने इस असमंजस को और गहरा किया है. ऐसे में बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन एक संतुलित संदेश देता है. पार्टी यह संकेत देती है कि बिहार संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही वह किसी एक नेता को समय से पहले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में स्थापित करने से भी बच रही है.

> भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपनी चौकाने वाली रणनीति को ही विस्तार दिया है. नितिन नबीन न तो राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थापित चेहरा हैं और न ही बिहार की राजनीति में उन्हें किसी बड़े जनाधार वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा है. इसके बावजूद उन्हें पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक ढांचे में शामिल किया जाना इस बात का संकेत है कि भाजपा में अब नेतृत्व चयन का आधार करिश्मा या चुनावी लोकप्रियता नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और शीर्ष नेतृत्व के प्रति भरोसा बन चुका है.

यह रणनीति कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व का भरोसा देती है और नेतृत्व को विकल्प खुले रखने की सुविधा भी. पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की नेतृत्व चयन नीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है. राष्ट्रपति चुनाव से लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री चयन तक पार्टी ने ऐसे फैसले किए, जिनकी पहले से कोई सार्वजनिक घोषणा या राजनीतिक तैयारी नजर नहीं आई. यह अप्रत्याशितता अब भाजपा की रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है. इससे नेतृत्व को यह लाभ मिलता है कि कोई भी नेता चुनावी जीत को व्यक्तिगत दावेदारी में नहीं बदल पाता. नितिन नबीन की नियुक्ति भी इसी रणनीति की निरंतरता में देखी जा सकती है. वे न तो किसी गुट के नेता हैं और न ही किसी क्षेत्रीय शक्ति केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे नेताओं की मौजूदगी संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि उनसे स्वतंत्र ध्रुवीकरण की आशंका कम रहती है. जातीय समीकरणों के संदर्भ में भी यह फैसला पूरी तरह निरपेक्ष नहीं है.

भाजपा अब इस यथार्थ को स्वीकार कर चुकी है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के बिना व्यापक राजनीतिक स्वीकार्यता संभव नहीं है. नितिन नबीन जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वह न तो अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है और न ही पूरी तरह हाशिये पर. इस तरह का चयन पार्टी को जातीय संतुलन साधने में मदद करता है, बिना किसी बड़े सामाजिक समूह को नाराज़ किए. यह नियुक्ति भाजपा के उस संगठनात्मक मॉडल को भी रेखांकित करती है, जिसमें नेतृत्व का मूल्यांकन राजनीतिक चमक के बजाय प्रशासनिक दक्षता और अनुशासन के आधार पर किया जाता है. पार्टी अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जो नीतियों पर सार्वजनिक प्रश्न उठाने के बजाय उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकें.

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नितिन नबीन को पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. यह पद उन्हें दृश्यता और जिम्मेदारी देता है, लेकिन अंतिम निर्णयों की शक्ति शीर्ष नेतृत्व के पास ही रहती है. इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा फिलहाल संगठन पर नियंत्रण को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. हालांकि, यह रणनीति अल्पकाल में संगठनात्मक स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन दीर्घकाल में यह प्रश्न भी खड़े करती है कि क्या केवल प्रबंधन और अनुशासन के सहारे जटिल लोकतांत्रिक राजनीति को साधा जा सकता है. क्या जनाधार, संवाद और राजनीतिक स्वायत्तता की भूमिका को पूरी तरह नियंत्रित नेतृत्व से प्रतिस्थापित किया जा सकता है. नितिन नबीन की नियुक्ति इन सवालों का सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन भाजपा की वर्तमान राजनीतिक मानसिकता को जरूर स्पष्ट करती है. यह किसी बड़े नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा नहीं, बल्कि नेतृत्व शैली मेंड्ड आए बदलाव का संकेत है. पार्टी अब चेहरों की राजनीति से अधिक संगठनात्मक नियंत्रण पर भरोसा कर रही है.